(b) Under 'Operation Black Board' scheme, the Government of India has provided assistance of Rs. 846.91 lakhs during 1991-92 and Rs. 1819.00 lakhs during 1992-93 (anticipated) to the State of Madhya Pradesh. Further, Central Government has provided funds to the State of Madhya Pradesh under following Centrally-sponsored schemes during 1991-92 and 1992-93 as Central assistance :

(Rs. in lakhs)

Programme	1991-92	1992-93
(i) National Malaria Eradication Programme	928.36	1203.15
(ii) National Leprosy Eradication Programme	208.62	199.00
(iii) National T.B. Control Programme	33.79	96.91
(iv) Natioal Programme for Control of Blindness.	198.95	146.76

(c) and (d) As may be seen from figures of expenditure in part (a) of the Question, the Government of Madhya Pradesh has spent almost all the amount earmarked during 1992-93.

उत्तर प्रदेश में बंजर भूमि का विकास

3254. **श्री राम करेश यादव :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में "बंजर भूमि का विकास" करने हेतु जिलावार कौन-कौन से क्षेत्र चुने गए हैं ;

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बंजर भूमि का विकास करने के लिए कुल कितनी धनराशि खर्च किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (परती भूमि विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कर्नल राम सिंह) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

रोजगार उपलब्ध कराने के लिये राज्य सरकारों को धनराशि का दिया जाना

@3255. **डा. जितेन्द्र कुमार जैन :**
श्री वीरेन जे. शाह :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने नवीनीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकारों को प्रत्येक विकास खंड में 5 लाख रुपए की दर पर 1752 विकास खंडों में वितरण करने हेतु धनराशि जारी कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में विस्तृत ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने यह अनुमान लगाया है कि यह धनराशि खर्च करके कितने कर्मकारों को रोजगार मिलने की संभावना है और उनमें से प्रत्येक को एक वर्ष में कितने दिन काम मिलने का अनुमान है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) 1993-94 के दौरान देश में पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली वाले 1752 खण्डों में सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत रोजगार उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार ने केन्द्रीय अंश के रूप में राज्य सरकारों को 5 लाख रुपए प्रति खंड के हिसाब से रिलीज किए हैं । वर्ष 1993-94 के दौरान सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत शामिल किए खण्डों की संख्या और अब तक रिलीज की गई राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है । (नीचे देखिए) ।

@पूर्वतः अतारांकित प्रश्न 2430, 20-12-1993 से स्थानांतरित ।

(ग) और (घ) सुनिश्चित रोजगार योजना का उद्देश्य वर्ष के गैर-कृषि मौसम के दौरान शारीरिक रूप से सक्षम उन ग्रामीण गरीबी, जो रोजगार के जरूरतमंद हैं तथा शारीरिक श्रम वाला कार्य करना चाहते हैं, के लिए 100 दिन का शारीरिक श्रम वाला सुनिश्चित रोजगार उपलब्ध कराना है । अब तक सुनिश्चित रोजगार योजना के कार्यान्वयन हेतु निधियों की केवल पहली किश्त रिलीज की गई है तथा आगे की रिलीजें पहले ही रिलीज की गई निधियों के उपयोग से परिलक्षित आवश्यकताओं के आधार पर दी जाएंगी चूंकि योजना का उद्देश्य उन सभी लोगों को, जो शारीरिक श्रम वाला काम करना चाहते हैं, सुनिश्चित रोजगार उपलब्ध कराना है, इसलिए पहले से रिलीज की गई राशि का इस्तेमाल करके रोजगार प्राप्त करने वाले संभावित मजदूरों की संख्या तथा प्रत्येक मजदूर को मुहैया कराए गए श्रम दिनों की संख्या का मूल्यांकन करने का प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण

1993-94 के दौरान सुनिश्चित रोजगार योजना के कार्यान्वयन हेतु चयनित खण्डों (पुनर्गठित सार्व-जनिक वितरण प्रणाली वाले खंड) को राज्यवार संख्या तथा इस हेतु रिलीज की गई धनराशि

क्रमांक	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	खंडों की सं.	केन्द्रीय अंश	राज्य का मैचिंग अंश	रिलीज की गई कुल धनराशि (लाख रुपयों में)
1.	आन्ध्र प्रदेश	120	600	150	750
2.	अरुणाचल प्रदेश	48	240	60	300
3.	असम	69	345	86.25	431.25
4.	बिहार	156	780	195	975.00
5.	गोआ	—	—	—	—
6.	गुजरात	97	495	121.25	606.25
7.	हरियाणा	44	220	55	275.00
8.	हिमाचल प्रदेश	7	35	8.75	43.75
9.	जम्मू और कश्मीर	34	170	42.50	212.50
10.	कर्नाटक	94	470	117.50	587.50
11.	केरल	21	105	26.25	131.25
12.	मध्य प्रदेश	223	1115	278.75	1393.75
13.	मणिपुर	22	110	27.50	137.50
14.	महाराष्ट्र	114	570	142.50	712.50
15.	मेघालय	30	150	37.50	187.50
16.	मिजोरम	20	100	25.00	125.00
17.	नागालैण्ड	28	140	35.00	175.00

1	2	3	4	5	6
18.	उड़ीसा	143	715	178.75	893.75
19.	पंजाब	—	—	--	—त
20.	राजस्थान	122	610	152.50	762.50
21.	सिक्किम	4	20	5.00	25.00
22.	तमिलनाडु	56	280	70.00	350.00
23.	त्रिपुरा	18	90	22.50	112.50
24.	उत्तर प्रदेश	145	725	181.25	906.25
25.	पश्चिम बंगाल	128	640	160.00	800.00
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2	10	--	10.00
27.	चंडीगढ़	--	--	--	—
28.	दादर और नगर हवेली	1	5	—	5.00
29.	दमन और दीव	1	5	--	5.00
30.	दिल्ली	--	--	—	—
31.	लक्षद्वीप	5	25	—	25.00
32.	पांडिचेरी	--	—	—	—
		1752	8760.00	2178.75	10938.75

राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड को सहायता अनुदान योजना के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्र

3256. **श्री ईश दत्त यादव :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड की सहायता अनुदान योजना के अन्तर्गत गत एक वर्ष के दौरान प्राप्त आवेदन पत्रों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) राज्यवार किन-किन संगठनों को कितनी-कितनी सहायता प्रदान की गई है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (परती भूमि विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कर्नल राम सिंह) : (क) राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड का नवसृजन करके इसे 7 सितम्बर, 1992 को ग्रामीण मंत्रालय के अधीन बंजर भूमि विकास विभाग में हस्तांतरित किया गया था। उसके हस्तांतरण के बाद से ही 31-10-93 तक अनुदान सहायता योजना के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों का राज्यवार ब्यौरा विवरण 1 में दिया गया है (नीचे देखिये)

(ख) राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड की अनुदान सहायता योजना के अन्तर्गत संस्थाओं के नाम और दी जाने वाली सहायता सहित राज्यवार ब्यौरे विवरण-2 तथा विवरण-3 में दिये गये हैं।